(ग) क्या यह सच है कि विज्ञान सलाहकार परिषद की राय में खाद्यान्नों के लिए निर्धारित किया यह लक्ष्य उस समय देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है ?

उप-प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) सन् 2000 ईसवी के लिए खाद्यान्न उत्पादन का कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। वैसे, सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगाए गए पूर्वानुमानों के अनुसार सन् 2000 ईसवी तक 235-240 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होने का अनुमान है। जब आठवीं पंचवर्षीय योजना को संशोधित किया जाएगा तब खाद्यान्न उत्पादन की यह अनुमानित मात्रा संशोधित हो सकती है।

(ग) विज्ञान सलाहकार परिषद ने बताया है कि इस शताब्दी के अंत तक खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य लगभग 250 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष हो सकता है।

(घ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है :--

(1) गहन खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्रों को अनुकूलतम बनाना।

(2) वर्षा के पूर्वानुमान लगाने में सुधार।

(3) बायोटैक्नोलांजी आनुवांशिक इंजीनियरिंग फोटोसिंथेसिस, टिशू कल्चर, जैविक कृमि नाशकों फौर औरोमोंस जैसे नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान कृषि उत्पादकता की वृद्धि में सहायता के लिए इनके उपयोग पर बल देना।

(4) बारानी खेती पर अनुसंधान को तेज करना और नई प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से खेत तक अंतरित करना, अधिक ऋण सुलभ करना और बारानी खेती वाले क्षेत्रों में विपणन सुविधाओं का विकास करना।

(5) सिंचाई और कृषि विस्तार सेवा सुधार के संबंध में आधुनिक प्रबन्ध तकनीकें आरम्भ करना तथा सहकारी आन्दोलन को मजबूत बनाना।

(6) उर्वरकों तथा अधिक उपज देने वाली बीजों की नई किस्मों का अधिक उपयोग और सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार तथा आठवीं योजना एवं नौवीं योजना के दौरान अपनाई जाने वाली विस्तृत कार्यनीतियां संबंधित योजना दस्तावेजों में दी जाएगी।

खाद्यान्नों का आयात

1298. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्नों का भरपूर उत्पादन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 में गेहूं, चावल और मक्का का अलग-अलग कितना-कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में खाद्यान्नों के भरपूर उत्पादन के बावजूद भी गत वर्ष अर्थात् 1988-89 में खाद्यान्नों का आयात किया गया ;

(घ) यदि हां, तो किस-किस देश से, किस-किस खाद्यान्न का कितनी-कितनी मात्रा में और कितने-कितने मूल्य पर आयात किया गया ; और

(ङ) ऐसे आयात किए जाने के क्या कारण थे ?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) वर्ष 1988–89 के दौरान देश में खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है।

(ख) (मिलियन मीटरी टन)
अखिल भारतीय उत्पादन

फसल	1987–88	1988–89
चावल	56.9	70.7
गेहूं	46.2	54.0
मक्का	5.7	8.3

(ग) से (ङ) जी हां, 1988–89 के दौरान भारत ने सरकार की ओर से अमेरिका से करीब 243.36 मिलियन अमेरिकी डालर की एफ. ओ. बी. लागत पर 20.11 लाख मीटरी टन गेहूं तथा करीब 166.76 मिलियन अमेरिकी डालर की एफ. ओ. बी. लागत पर थाईलैंड से 6.84 लाख मीटरी टन चावल का आयात किया।

ये आयात इसलिए किए गए क्योंकि 1987–88 के सूखे के प्रभाव के कारण खरीद कम होने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कार्यक्रमों के लिए अधिक मांग होने की वजह से जमा-भंडार बहुत कम हो गये थे।

वर्ष 1987 में भारत में सूखा पड़ने पर अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी राज्य सरकार [illegible] जिस विदेशी अनुदान करार के अन्तर्गत 4 लाख मीटरी टन मक्का का अनुदान भारत को किया था। इसमें से 2 लाख मीटरी टन मक्का 1988 में आयात किया गया था तथा शेष 2 लाख मीटरी टन का 1989 में। सहमत व्यवस्था के अनुसार यह मक्का निःशुल्क दिया गया था। लेकिन, भारत सरकार को ढुलाई का भाड़ा और वितरण तथा परिवहन आदि का सारा अन्य खर्च वहन करना पड़ा। देश में मक्का की उपलब्धता में वृद्धि के लिए 1987 में नैफेड को अर्जेन्टीना से वाणिज्यिक आधार पर मक्का का आयात करने की अनुमति भी दी गई थी। तदनुसार 1988 में 78,189 मीटरी टन मात्रा का आयात किया गया।

बाल कृष्ण समिति द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की आलोचना

1299. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
श्री राम नरेश यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल कृष्ण कमेटी (सरकारिया आयोग) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की तीखी आलोचना की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में नियोजित विकास में धीमी गति का कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उसको सौंपे गए कर्तव्यों का उचित प्रकार से पूरा न किया जाना है ; यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में आमूल-चूल परिवर्तन करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) दिल्ली के ढांचे संबंधी पुनर्गठन समिति ने महसूस किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के सुनिश्चित नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त समय के साथ-साथ अन्य कार्य लिए और इससे उसके कार्य करने में गम्भीर हानि पहुंची है यह सिफारिश की गयी है कि ऐसे अतिरिक्त कार्यों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से वापस ले लिया जाय। समिति की सिफारिशें जांचाधीन हैं।